



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 128]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत अधिप्राप्त के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु
दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 23/11/2004-आर एंड आर (खंड VI).—वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 19-1-2005 को संकल्प सं. 23/11/2004-आर एंड आर (खंड-II) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I खंड 1) में प्रकाशित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों को दिनांक 30-3-2006 के राजपत्र संकल्प सं. 23/11/2004-आर एंड आर (खंड-IV), दिनांक 18-8-2006 के संकल्प सं. 23/11/2004-आर एंड आर (खंड-V) और दिनांक 27-9-2007 के संकल्प सं. 23/11/2004-आर एंड आर (खंड-VI) के तहत तीन बार संशोधित किया गया है।

2. उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, नामशः

2.1 निम्नलिखित अनुच्छेद खंड 2.1 के आरंभ में जोड़ा जाता है :—

विद्युत अधिनियम की धारा 10 व्यवस्था करती है कि उत्पादन कम्पनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार किसी लाइसेंसी को विद्युत की आपूर्ति कर सकती है और धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, किसी भी उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति कर सकती है। राष्ट्रीय विद्युत नीति में अनुबंधित है कि नई उत्पादन क्षमता का एक भाग, यों कहें पन्द्रह प्रतिशत (15%) बाजार विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घावधि पीपीए से बाहर बेचा जा सकता है। टैरिफ नीति (जैसे कि मार्च, 2008 में संशोधित है) में जल विद्युत परियोजनाओं के अपने टैरिफ उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित करवाने की व्यवस्था भी की गई है, बशर्ते कि इसके साथ-साथ परियोजना की कुल बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा के कम से कम साठ प्रतिशत (60%) के लिए दीर्घावधि पीपीए हो। दीर्घावधि विद्युत क्रय करार से बाहर विद्युत की बिक्री सामान्यतया एक वर्ष से कम अवधि के लिए होती है।

2.2 निम्नलिखित अनुच्छेद को खंड 2.1 में स्पष्टीकरण के पश्चात् जोड़ा जाता है:-

केन्द्र सरकार जैसे और जब भी उपयुक्त समझे, विद्युत अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत एक वर्ष से कम की अवधि के लिए विद्युत की प्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश जारी करेगी । वे दिशा-निर्देश समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क नीति में यथावर्णित, दीर्घावधि पीपीए से बाहर प्राप्त की जाने वाली विद्युत पर लागू होंगे ।

2.3 खंड 2.2 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है:-

तथापि, बेस लोड अथवा व्यस्ततम कालीन भार अथवा मौसमी भार जरूरतों के लिए; मामले के अनुसार, पृथक आर एफ पी को उपयोग में लाया जाएगा ।

2.4 खंड 3.1 के उप खंड (iii) ख को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

ईंधन की कीमत में अंतरण हेतु, ईंधन विशेष अधिप्राप्त जांच के मामले में, यदि यह कीमत सरकार, सरकार के स्वामित्व वाली संबंधित कोयला कंपनी, सरकार द्वारा अनुमोदित मैकेनिज्म अथवा ईंधन नियामक (मामला-2 के अंतर्गत) द्वारा निर्धारित नहीं की गई है ।

2.5 खंड 3.2 का प्रथम पैरा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(I) प्राप्त की जा रही विद्युत की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित करने और प्राप्तकर्ता के अटल इरादे के बारे में बोलीदाताओं के संदेह को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्यकलापों को समय पर पूरा कर लिया जाए । दीर्घावधि परियोजनाओं, जिनके लिए पूर्व निर्धारित स्थलों को उपयोग में लाया जाना है (मामला-2), के बारे में प्राप्तकर्ता अथवा प्राप्तकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रक्रिया से जुड़ी हुई निम्नानुसार उपलब्धियों के साथ-साथ निम्नांकित परियोजना के प्रारंभिक कार्यकलापों को पूरा कर लिया जाना चाहिए ।

2.6 खंड 3.2 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है:-

(II) मामला 1 अधिप्राप्त में, बोली प्रक्रिया में बोलीदाता की गंभीर भागीदारी और विद्युत की आपूर्ति की शुरुआत समय पर सुनिश्चित करने के लिए, यदि आपूर्ति किसी स्टेशन से प्रस्तावित की जाती है तो बोलीदाता से यह अपेक्षा होगी कि वह अपनी बोली के साथ नीचे (i) से (v) में उल्लिखित मामलों के बारे में परियोजना की आरंभिक गतिविधियों हेतु शुरू किए गए विशेष कार्यों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करे ।

- i) स्थल निर्धारण और भूमि अधिग्रहण: पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्दिष्टानुसार भूमि की जरूरत पर विचार किया जाएगा । बोलीदाता को भूमि का अधिग्रहण करना होगा और भूमि के कम से कम 50% क्षेत्र पर कब्जा लेना होगा । भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत अधिग्रहीत व की जाने

वाली भूमि के मामले में बोलीदाता भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के खंड 4 के अंतर्गत ऐसी भूमि के लिए जारी अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करेगा। अन्य सभी मामलों में बोलीदाता संबंधित और अधिग्रहण/स्वामित्व/भूमि प्रदान करने के लिए सक्षम राजस्व/पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। इन साक्ष्यों के साथ विकासकर्ता को शपथपत्र देना होगा, जिसमें विद्युत स्टेशन के लिए अधिग्रहीत कुल भूमि की सूची होगी।

- ii) विद्युत स्टेशन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति:- बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार में अंतिम अनुमोदन प्रदान करने हेतु उत्तरदायी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- iii) विद्युत स्टेशन के लिए भूमि हेतु वन स्वीकृति (यदि लागू हो): बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार में अंतिम अनुमोदन प्रदान करने हेतु उत्तरदायी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से वन स्वीकृति हेतु अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- iv) ईंधन व्यवस्था: विद्युत स्टेशन की संस्थापित कुल क्षमता से पीपीए की अवधि तक विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित ईंधन के परिमाण हेतु, ईंधन व्यवस्था करनी होगी।

- घरेलू कोयला के मामले में बोलीदाता को खान आबंटन अथवा ईंधन अनुबंध के जरिए ईंधन की निश्चित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- आयातित कोयले के मामले में बोलीदाता को या तो खानों का अधिग्रहण करना होगा, जिनमें परियोजना के लिए अपेक्षित कोयले की मात्रा का कम से कम 50% क्षमता का प्रमाणिक भण्डार हो अथवा कम से कम पांच (5) वर्ष अथवा पीपीए की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए अपेक्षित कोयला परिमाण, कम से कम 50% हेतु ईंधन आपूर्ति करार करना होगा।
- घरेलू गैस के मामले में बोलीदाता को दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति करार के जरिए निश्चित ईंधन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- आरएलएनजी के मामले में, बोलीदाता को कम से कम 5 वर्ष अथवा पीपीए की अवधि, जो भी कम हो के लिए अपेक्षित ईंधन के परिमाण का कम से कम 50% के लिए ईंधन आपूर्ति करार के जरिए ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

- v) जल संयोजन:- बोलीदाता को विद्युत स्टेशन के लिए अपेक्षित जल की मात्रा के लिए संबंधित राज्य के सिंचाई विभाग अथवा किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन लेना होगा।

यदि बोलीदाता ट्रेडिंग लाइसेंस है तो उसे बोली में प्रस्तावित विद्युत की मात्रा हेतु विशेष विद्युत खरीद करार करना होगा और बोली के एक भाग के रूप में उसकी प्रति उपलब्ध करानी होगी। ऐसे मामले में बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्था, जिसके साथ उसने विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत क्रय करार किया है, की आरंभिक परियोजना संबंधी गतिविधियां, जैसा कि उपर्युक्त (i) से (v) में उल्लेख है, पूरी हो गयी है। इसके अलावा बोलीदाता विद्युत स्टेशन विकसित कर रही संस्था से यह दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा कि परियोजना स्थापित करने संबंधी आरंभिक गतिविधियां जैसा कि ऊपर (i) से (v) में उल्लेख है, पूरी हो गयी है।

मौजूदा उत्पादक स्टेशन से प्रस्तावित की जा रही आपूर्ति के मामले में बोलीदाता को उत्पादक स्टेशन के व्यवसायिक प्रचालन के समर्थन में, जैसा भी मामला हो, आरएलडीसी/एसएलडीसी को भेजे गए घोषणापत्र के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

2.7 खंड 4.1 के बाद में निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए प्रत्येक भुगतान अवधि (एक माह से अधिक नहीं) के लिए टैरिफ का भुगतान और निर्धारण किया जाएगा। टैरिफ की पृथक क्षमता और ऊर्जा घटक सामान्य रूप से बहुविधि टैरिफ ढांचे अथवा बोली प्रक्रिया का आधार होगा।

मामला-2 के अंतर्गत अधिप्राप्ति, जहाँ प्राप्तकर्ता सहमति हेतु कैप्टिव ईंधन स्रोत (जैसे कैप्टिव कोयला खान) का प्रस्ताव करता है और अधिप्राप्ति अनुयोग के अंतर्गत कवर किए गए विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग करता है, का भी बहुविधि टैरिफ ढांचा होगा, जिसमें टैरिफ की क्षमता और ऊर्जा घटक पृथक रूप से होगा।

2.8 खंड 4.3 में दूसरा प्रावधान जोड़ा जाना:

ऊर्जा प्रभार भुगतान में विदेशी विनिमय दर परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाएगी [पैरा 4.11 (iii) के अनुसार], यदि बोलीदाता मामला-1 के अंतर्गत दीर्घावधिक अधिप्राप्ति के लिए आयातित कोयले अथवा आयातित गैस (आर एल एन जी) का प्रयोग करके विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव करता है।

2.9 खंड 4.4 को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्षमता प्रभार का भुगतान, रुपये/कि०वा०घं० में बताए गए (कोट किए गए) प्रभारों के अनुसार वास्तविक उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा और वह मानकीय उपलब्धता तक सीमित होगा। मामला 1 तथा ताप केंद्रों के लिए मानकीय उपलब्धता अधिकतम 85% है। मामला-2 के अंतर्गत जल विद्युत केंद्रों के लिए, मानकीय उपलब्धता जैसा कि बोली प्रक्रिया के समय विद्यमान केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट वार्षिक संयंत्र उपलब्धता के संघटक स्तर के अनुरूप लागू की जाएगी। टैरिफ के क्षमता संघटक में पृथक अवृद्धिकारी (नियत) और वृद्धिकारी (सूचकांकित) संघटक हो सकते हैं। वृद्धिकारी संघटक की वृद्धि के लिए अपनाया जाने वाला सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अथवा उपर्युक्त दोनों संघटकों का संयोजन होगा और आधार वर्ष बोली दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

2.10 खंड 4.5 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

मानकीय उपलब्धता से अधिक उपलब्धता के लिए क्षमता प्रभार, क्षमता प्रभार के अवृद्धिकारी संघटक का पूर्व-निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। लागू प्रतिशत आरएफपी में निर्दिष्ट

किया जाएगा और वह क्षमता प्रभार के अवृद्धिकारी संघटक के 40% तक सीमित होगा। अधिप्राप्तिकर्ता को मानकीय उपलब्धता से अधिक उत्पादित ऊर्जा पर अस्वीकृति का पहला अधिकार होगा। अगर वास्तविक उपलब्धता मानकीय उपलब्धता से कम है तो क्षमता प्रभार उपलब्धता की तुलना में कमी के लिए देय नहीं होगा। किसी मामले में अगर पूर्वनिश्चित स्तर से उपलब्धता कम है (जो कि आरएफपी में निश्चित है, उस मानकीय उपलब्धता से 5% तक कम होने पर) ऐसे मामले में पूर्व निश्चित स्तर से कमी की सीमा तक की अनुपलब्धता पर क्षमता प्रभार के 20% की दर पर दंड लागू होगा।

2.11 खंड 4.11 के उप खंड (III) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

मामला-2 में ऐसे मामले में, जहां अधिप्राप्तिकर्ता तटीय विद्युत स्टेशन में प्रयोग के लिए आयातित ईंधन के प्रयोग के लिए अधिदेशित है, प्रापण की पूछताछ अथवा जहां बोलीदाता मामला-1 में आयातित ईंधन वाले विद्युत केंद्र से आपूर्ति करने का चयन करता है, में आरएफपी में अभिज्ञात सूचकांकों के अनुसार वृद्धि किए जाने वाले पहले वर्ष के लिए आधार ऊर्जा प्रभार हेतु बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं। ऐसे ऊर्जा प्रभार में निम्नलिखित तीन संघटक होंगे-

- (क) अमरीकी डॉलर/यूनिट में आयातित ईंधन संघटक।
- (ख) अमरीकी डॉलर/यूनिट में ईंधन की दुलाई संघटक।
- (ग) भारतीय रुपये/यूनिट में अंतर्देशीय ईंधन प्रहस्तन संघटक।

2.12. खंड 4.11 के उप खंड (iii) के बाद में निम्न उप खंड (iv) को जोड़ा जाना है-

(iv) जहां घरेलू कोयला/गैस/आयातित ईंधन से लिकेज आधारित परियोजनाओं के किसी मामले में आंतरिक परिवहन वाला घटक शामिल होगा, आंतरिक परिवहन पर एक अलग वृद्धि घटक रुपये/यूनिट में लागू होगा।

उपर्युक्त (iii) एवं (iv) के प्रत्येक संघटक में पृथक गैर-वृद्धि योग्य (नियत) और वृद्धि योग्य (सूचकांकित) उप संघटक हों। इन संघटकों के वृद्धि योग्य उप संघटकों के लिए वृद्धि सूचकांक इस प्रकार के होंगे जैसे कि सीईआरसी द्वारा पैरा 5.6 (vi) के तहत अधिसूचित किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि बोलीदाताओं के पास, ठेके के प्रत्येक वर्ष के लिए स्थायी ऊर्जा प्रभार दरें देने का विकल्प होगा।

2.13 खंड 4.13 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

अधिप्राप्तकर्ता मामला 2 के तहत जल विद्युत की बोलियां आमंत्रित करता है तो, हाइड्रोलॉजिकल जोखिम का वहन प्रापक द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी परियोजना के हाइड्रोलॉजिकल आंकड़े अधिकृत स्रोतों पर आधारित हों तथा पक्षों को पहले से ही ज्ञात हों।

मामला 2 के तहत किसी भी प्रकार का हाइड्रोलॉजिकल लाभ जिसके परिणामस्वरूप डिजाइन ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा उपलब्धता हो, प्रापक को बिना किसी प्रभार के दिया जाएगा। यदि बोलीदाता मामला-1 के तहत हाइड्रो ऊर्जा प्रस्तुत करता है तो हाइड्रोलॉजिकल जोखिम बोलीदाता द्वारा उठाया जाएगा। मामला-1 तथा मामला-2 दोनों में ही जल विद्युत परियोजना का भूगर्भीय जोखिम विकासकर्ता द्वारा उठाया जाएगा।

2.14 खंड 4.15 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

जिन मामलों में प्रापण प्रक्रिया में बोलीदाताओं को संयुक्त क्षमता तथा ऊर्जा प्रभार प्रस्तुत करने की अनुमति हो, वहां प्रस्तावित प्रभार विद्युत क्रय करार (पीपीए) की अवधि के प्रत्येक वर्ष में अपरिवर्तनीय रहेंगे, तथा विक्रेता द्वारा प्रप्रभार में मूल्य बोली में दी गई दरों से ज्यादा बढ़ोत्तरी करने की कोई अनुमति नहीं होगी।

2.15 खंड-5 में "बोली प्रक्रिया" शीर्षक के पश्चात "दो स्तरीय प्रक्रिया" शब्द हटा दिए गए हैं।

2.16. खंड 5.1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

मामला-2 के तहत दीर्घकालिक प्रापण हेतु, इन दिशानिर्देशों के तहत बोली प्रक्रिया के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के लिए अलग-अलग चरण की द्वि-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रापक यदि चाहे तो मामला-1 के तहत, आरएफपी तथा आरएफक्यू प्रक्रियाओं को संयुक्त करते हुए, दीर्घकालीन अथवा मध्यावधिक प्रापण के लिए एक स्तरीय निविदा प्रक्रिया अपना सकता है। तथापि, जैसा कि पहले पैरा 2.2 में विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रापक बेस लोड अथवा पीक लोड अथवा सीज़नल लोड आवश्यकताओं, जैसा भी मामला हो, के प्रापण के लिए अलग आरएफपी प्रक्रियाएं अपनाएं। प्रापक अथवा अधिकृत प्रतिनिधि इन दिशानिर्देशों तथा मानक बोली दस्तावेजों के अनुरूप आरएफक्यू तथा आरएफपी (एकल स्तर प्रक्रिया में केवल आरएफपी) को शामिल करते हुए बोली प्रस्ताव तैयार करेगा।

2.17 खंड 5.2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

प्रापक आरएफक्यू (एकल स्तर प्रक्रिया में आरएफपी) का विस्तृत प्रचार करने के लिए इसकी सूचना न्यूनतम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, कंपनी की वेबसाइट पर तथा अधिमानतः व्यापार पत्रिकाओं में भी प्रकाशित करेगा। बोली प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के माध्यम से की जाएगी। आरएफक्यू (एकल चरण प्रक्रिया में आरएफपी) को जारी करने के उद्देश्य से बोलीदाता द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम शर्तों को प्रापक द्वारा आरएफक्यू (एकल चरण प्रक्रिया में आरएफपी) सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

2.18. खंड 5.4 का प्रथम वाक्य तथा इसके उपखंड (झ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

प्रापक द्वारा आरएफक्यू (एकल स्तर प्रक्रिया में आरएफपी) में प्रदान किए जाने वाले मानक प्रलेखों में यह शामिल होगा,

(I) प्रापक की आवश्यकताओं की परिभाषा में यह शामिल है-

- मेगावाट में क्रय हेतु प्रस्तावित बिजली की मात्रा। बोलीदाताओं को नम्यता प्रदान करने के लिए वह परास क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाए जिसके अंदर बोलियां स्वीकार्य होंगी। इसके अतिरिक्त, प्रापक बोलीदाताओं को बताई गई न्यूनतम मात्रा के शर्ताधीन, निविदित मात्रा के अंश के लिए बोली देने की भी छूट प्रदान करे;
- प्रापक लोड की आवश्यकता की प्रकृति (क्या बेस लोड है, सीज़नल लोड है अथवा दिन के समय का लोड है), जिन महीनों में सीज़नल प्रापण के लिए प्रस्तावित विद्युत का ठेका किया जा रहा है उनकी अवधि तथा उन घंटों की अवधि जिसके लिए दिन के समय की आवश्यकता के लिए विद्युत का ठेका करने का प्रस्ताव है, विनिर्दिष्ट करेगा;
- प्रस्तावित ठेके की अवधि (जहां तक मामला 2 में संभव है, दीर्घकालीन प्रापण के मामले में परियोजना के जीवनकाल के साथ समरूप ठेका करना यथोचित है) बोलीदाता को अपने द्वारा प्रस्तावित ईंधन पर निर्भर परियोजना के प्रत्याशित जीवनकाल के लिए, प्रभार रचना का भाव देना अपेक्षित होगा। गैस(तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं का 15 वर्षों का, कोयला आधारित परियोजनाओं का 25 वर्षों का तथा जल विद्युत परियोजनाओं का 35 वर्ष का प्रत्याशित जीवनकाल आकलित किया गया है। मामला 1 में, प्रापक विनिर्दिष्ट बोली प्रक्रिया के लिए ठेके की अवधि विनिर्दिष्ट करने के लिए मुक्त होगा चाहे विद्युत आपूर्ति का स्रोत कुछ भी हो;
- मानकीय उपलब्धता आवश्यकताएं जिसकी पूर्ति विक्रेता द्वारा की जानी है (व्यस्ततम तथा गैर-व्यस्ततम घंटों के लिए अलग-अलग, यदि आवश्यक हो तो);
- यदि प्रापण जानकारी से संबंधित हो तो, व्यस्ततम तथा गैर-व्यस्ततम घंटों की परिभाषा;
- आपूर्ति प्रारंभ होने की प्रत्याशित तिथि
- वे स्थान जहां बिजली दी जानी है;
- जहां लागू हो, वहां प्रापक बोलीदाताओं द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निर्माण संबंधी माइलस्टोन निर्धारित कराए।
- बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली वित्त संबंधी आवश्यकताओं में, जैसा कि बोली दस्तावेजों में बताया गया है, आवश्यक सबूतों सहित न्यूनतम शुद्ध मूल्य, आय इत्यादि शामिल हैं।

2.19. खंड 5.5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

आरएफपी उन सभी बोलीदाताओं को, जो द्वि-चरण बोली प्रक्रिया में, आरएफक्यू चरण पर अर्हक हुए हैं, को जारी किया जाएगा। अगर बोलीदाता कोई परिवर्तन चाहता है और अधिप्राप्तिकर्ता यह पाता है कि परिवर्तन उचित है तो अधिप्राप्तिकर्ता परिवर्तनों के लिए सहमत होने से पहले उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा। स्पष्टीकरण/संशोधित बोली दस्तावेज़ उन सभी को जिन्होंने आरएफपी खरीदा था, परिवर्तन और स्पष्टीकरण के बारे में सूचित करते हुए वितरित किये जायेंगे और उपयुक्त आयोग को भी सूचना भेजी जाएगी। अंतिम विद्युत क्रय करार (पीपीए) भी अधिप्राप्तिकर्ता की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जहां भी संशोधित बोली दस्तावेज़/संशोधन जारी किए जाते हैं, वहां अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेज़ जारी करने के बाद बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के लिए द्वि-स्तरीय बोली प्रक्रिया के मामले में न्यूनतम साठ (60) दिनों का तथा एकल स्तरीय बोली प्रक्रिया के मामले में न्यूनतम पैंतालीस (45) दिनों का समय दिया जाएगा। तथापि, आरएफपी दस्तावेज़ों में ऐसे किसी संशोधन के बाद आरएफपी बोलियों की प्रस्तुति करने के लिए कम समय उन सभी पूर्व अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की लिखित सहमति के साथ दिया जाए जिन्होंने आरएफपी खरीद लिए हैं।

2.20 खंड 5.6 के उप खंड (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पीपीए चयनित बोलीदाता के साथ हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है:

बोली दस्तावेज़ों में प्रस्तावित माडल पीपीए इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर संशोधित किया जाए और आरएफपी का उत्तर देने वाले सभी पक्षों को प्रदान किया जाएगा। आर एफ पी चरण के पश्चात् कोई और संशोधन नहीं किया जाएगा।

2.21 खंड 5.6 के उप खंड (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अधिप्राप्तिकर्ता द्वारा भुगतान उपलब्ध कराई जानी है-

बोली दस्तावेज़ों में दर्शायी गई भुगतान सुरक्षा को बोली प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर तथा बोली दस्तावेज़ों में निर्दिष्टानुसार संशोधित किया जा सकता है। तथापि, भुगतान सुरक्षा में, और कोई संशोधन आर एफ पी चरण के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

2.22 खंड 5.6 के उपखंड (iv) के दूसरे पैरा को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

उन मामलों को छोड़कर जहां कैप्टिव ईंधन स्रोत प्रस्तावित किया जाता है, अन्य मामलों में बोली मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू बाजार जैसी भी स्थिति हो, में उपर्युक्त ईंधन सूची (जैसी कि आरएफपी में चिह्नित की गई है) की वृद्धि दर, जो कि ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर समय-समय पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित की गई हो, को बोलीदाताओं द्वारा लगाए गए ऊर्जा प्रभार (खंड 4.2 में विनिर्दिष्ट

मामलों में लगाया गया ऊर्जा प्रभार) को बढ़ाने में उपयोग किया जाएगा। खंड 4.11 (III) और (iv) के प्रावधान उन मामलों में बोलियों के मूल्यांकन में भी लागू होंगे जहां प्राप्तकर्ता तटीय विद्युत स्टेशनों के लिए आयातित ईंधन के उपयोग को अनिवार्य मानता है। किंतु उन मामलों में, जहां बोलीदाता प्रस्तावित आपूर्ति के प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित ऊर्जा प्रभारों का हवाला देता है वहां बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा प्रभारों को बोली मूल्यांकन के लिए अपनाया जाएगा।

2.23. खंड 5.6 के उपखंड (vi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित जाता है-

निम्नलिखित को प्रत्येक छह माह के पश्चात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित एवं अद्यतन किया जाएगा:

- 1) घरेलू कोयले के लिए वृद्धि दर। (मूल्यांकन एवं भुगतान के लिए पृथक-पृथक रूप से)।
- 2) घरेलू गैस के लिए वृद्धि दर (मूल्यांकन एवं भुगतान के लिए पृथक-पृथक रूप से)।
- 3) आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धि योग्य उप घटकों हेतु वृद्धि दरें।
- 4) कोयले के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रभारों हेतु वृद्धि दरें (मूल्यांकन एवं भुगतान के लिए पृथक-पृथक रूप से)।
- 5) गैस के लिए देशी परिवहन प्रभारों हेतु स्फीति दरें (मूल्यांकन एवं भुगतान के लिए पृथक-पृथक रूप से)।
- 6) आयातित गैस पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धि योग्य उप घटकों के लिए वृद्धि दर (मूल्यांकन एवं भुगतान के लिए पृथक-पृथक रूप से)।
- 7) वृद्धि दर सूचीबद्ध क्षमता प्रभार घटक पर लागू किया जाएगा।
- 8) वृद्धि दर को कैप्टिव ईंधन स्रोत के मामलों में सूचीबद्ध ऊर्जा प्रभार घटक पर लागू किया जाएगा।
- 9) छूट दर का प्रयोग बोली मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।
- 10) डॉलर-रूपये विनिमय परिवर्तन दर (मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ)।
- 11) मानकीय पारेषण प्रभारों हेतु वृद्धि (मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ)।

2.24. खंड 5.14 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

मामला-1 के अंतर्गत प्राप्ति के मामलों में,

(I) बोलीदाता अंतर्संबंध बिंदु अर्थात् वह बिंदु जहां उत्पादन स्टेशन की विद्युत लाइनें अंतः/अंतर राज्य पारेषण नेटवर्क से जुड़ती हैं, पर विद्युत की कीमत को बताएगी (कोट करेगा)। बोली मूल्यांकन की प्रक्रिया में मानकीकरण के उद्देश्य हेतु टैरिफ प्राप्तकर्ता राज्य में एसटीयू नेटवर्क के साथ अंतरापृष्ठ डिलीवरी प्वाइंट बिंदु पर तुलना की जाएगी जहां

विद्युत की डिलीवरी प्राप्तकर्ताओं को की जाएगी। प्राप्तकर्ता के राज्य में उत्पादन स्रोत हेतु डिलीवरी प्वाइंट उत्पादन स्विचयार्ड होगा। बोली मूल्यांकन में सीईआरसी द्वारा उपलब्ध कराई गई संबंधित वृद्धि के साथ अंतःक्षेप बिंदु अर्थात् सीटीयू इंटरफेज बिंदु से सुपुर्दगी बिंदु तक नियामक पारेषण प्रभारों, यदि कोई है, पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। इंटरकनेक्शन प्वाइंट से डिलीवरी प्वाइंट तक पारेषण हानियों, जैसी कि समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं, पर भी मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा और अंतिम लेवलाइज्ड टैरिफ में प्रतिबिंबित किया जाएगा।

11) अंतःक्षेपण बिंदु से डिलीवरी प्वाइंट तक वास्तविक पारेषण प्रभार, जैसा कि समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, प्राप्तकर्ताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। अंतःक्षेपण बिंदु तक के प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

2.25. खंड 5.16 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

यदि इन दिशानिर्देशों से कोई विचलन होता है तो यह समुचित आयोग के पूर्व अनुमोदन से होगा। समुचित आयोग उचित समय के भीतर जो कि 90 दिन से अधिक न हो बोली दस्तावेजों के संशोधन पर निर्णय करेगा।

2.26. खंड 5.19 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-य

एकल चरण की बोली प्रक्रिया में, आरएफपी दस्तावेज को जारी करने तथा बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख के बीच 75 दिन की न्यूनतम अवधि की अनुमति दी जाएगी। बोली प्रक्रिया के लिए समय सारणी अनुबंध-11 में दर्शायी गई है। सामान्य परिस्थितियों में, बोली प्रक्रिया 120 दिन की अवधि में पूरी होने की संभावना है।

प्राप्तकर्ता अनुबंध-11 में दर्शायी गई समय-सीमा से अधिक समय-सीमा दे सकता है। किंतु यदि बोली प्रक्रिया में 195 दिन से अधिक का समय लगने की संभावना हो तो खंड 5.16 के अनुसार समुचित आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

2.27. खंड 6.1 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित जाता है-

विद्युत क्रय करार आरएफपी बोली दस्तावेजों में अंतिम रूप के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चयनित बोलीदाता/एसपीवी (मामला-2 के अंतर्गत में चयनित बोलीदाता द्वारा अधिग्रहण के पश्चात्) के साथ हस्ताक्षरित किया जाएगा।

इन दिशानिर्देशों के खंड 3.4 में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए पीपीए तथा अन्य परियोजना दस्तावेजों को आरएफपी बोलियों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख से पूर्व एसपीवी तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा निष्पादित किया जाए।

2.28 खंड 6.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

बोली प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात्, आर एफ पी बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति आर एफ पी दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार बोली प्रक्रिया मूल्यांकन की पुष्टि पर उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान करेंगी। अभिप्राप्तकर्ता इन दिशानिर्देशों को बोली प्रक्रिया की पुष्टि पर प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

2.29. वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुबंध-II को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है-

अनुबंध-II -एकात्मक स्तर की बोली प्रक्रिया के लिए समय तालिका

क्रम सं०	विषय	बोली के प्रस्तुतीकरण से पूर्व बोलीदाता द्वारा पूरा की जाने वाली गतिविधियां	शून्य तारीख से व्यतीत किया गया समय
1.	आरएफपी जारी किए जाने की तारीख		शून्य तारीख
2.	बोली स्पष्टीकरण सम्मेलन आदि और आरएफपी का संशोधन		**
3.	आरएफपी बोली प्रस्तुतीकरण	<ul style="list-style-type: none"> • भूमि: अधिग्रहण होना चाहिए और भूमि के कम से कम 50% क्षेत्र पर स्वामित्व होना चाहिए। धारा 4 की अधिसूचना प्रस्तुत की जाएगी यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत अधिग्रहीत की जाती है। • पर्यावरणीय, स्वीकृति संबंध प्राधिकारी को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। • वन स्वीकृति (यदि अपेक्षित हो) संबंध प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। • ईंधन व्यवस्था- खान आबंटन/ईंधन लिकेज/ईंधन आपूर्ति करारों के माध्यम से ईंधन व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। • जल लिकेज- संबंधित राज्य सिंचाई विभाग अथवा अन्य किसी प्राधिकारी का अनुमोदन उपलब्ध होना चाहिए। 	75 दिन

4.	बोलियों का मूल्यांकन और आशय पत्र का जारी किया जाना ।	100 दिन
5.	विद्युत क्रय करार प्रभावी होता है: करारों पर हस्ताक्षर: I) विद्युत क्रय करार, एस्करो करार, भाराक्रांत करार और कोई अन्य करार जो कि लागू हो (यदि ये खंड 3.4 के अंतर्गत पहले से ही हस्ताक्षरित नहीं किए गए हैं) । II) हिस्सा क्रय करार का हस्ताक्षरित किया जाना और एसपीवी का स्थानांतरण, यदि लागू हो ।	120 दिन

आरएफपी दस्तावेज में किसी परिवर्तन की स्थिति में, प्राप्तकर्ता बोलीदाताओं को खंड 5.5 के अनुसार अतिरिक्त समय देगे ।

टिप्पणी- यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधिप्राप्तकर्ता स्थिति से पूर्व पूरे किए जाने हेतु अपेक्षित गतिविधियों को प्राप्त करने में विलंब के कारण बोली प्रक्रिया में किसी विषय के लिए अतिरिक्त समय देता है तो इस प्रकार के अतिरिक्त समय को इन दिशानिर्देशों से किसी भी प्रकार से विचलन नहीं माना जाएगा । हालांकि, यदि मामला-1 प्राप्ति के अंतर्गत बोली प्रक्रिया में 195 दिन से अधिक का समय लगने की संभावना हो तो इसके लिए खंड 5.16 के अनुसार उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

MINISTRY OF POWER**RESOLUTION**

New Delhi, the 27th March, 2009

**Amendment to the Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for
Procurement of Power by Distribution Licensees**

No. 23/11/2004-R&R (Vol. VI).—The guidelines for determination of tariff by bidding process for procurement of power by Distribution Licensees have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide Resolution No. 23/11/2004-R&R (Vol. II) published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I—Section 1) on 19th January, 2005. These guidelines have been amended thrice vide Gazette Resolution No. 23/11/2004-R&R (Vol. IV) dated 30th March, 2006, Resolution No. 23/11/2004-R&R (Vol. V) dated 18th August, 2006 and Resolution No. 23/11/2004-R&R (Vol. IV) dated 27th September, 2007.

2. The following further amendments are hereby made in the said guidelines namely:-

2.1 **The following paragraph is added at the beginning of clause 2.1:**

Section 10 of the Electricity Act provides that a generating company may supply electricity to any licensee in accordance with the Act and rules and regulations made there under and may, subject to the regulations made under sub-section (2) of Section 42, supply electricity to any consumer. The National Electricity Policy stipulates that a part of new generating capacity, say fifteen percent (15%) may be sold outside long-term PPAs in order to promote market development. The Tariff Policy (as amended in March 2008) also provides for hydro electricity projects to have their tariffs determined by the Appropriate Commission provided inter-alia, it has long-term PPA for at least sixty percent (60%) of the total saleable design energy of the project. The sale of electricity outside long-term PPAs is usually for a period less than one (1) year.

2.2 **The following paragraph is added after the Explanation in clause 2.1:**

As and when considered appropriate, the Central Government would issue the guidelines for procurement of electricity for a period of less than one (1) year under the provisions of Section 63 of the Electricity Act. Those guidelines would be applicable to the electricity to be procured outside the long-term PPA as stipulated, from time to time, in the National Electricity Policy and Tariff Policy.

1228 GI/09-4

2.3 The following paragraph is added at the end of clause 2.2:

However separate RFP shall be used for procuring base load or peak load or seasonal load requirements as the case may be.

2.4 The sub-clause (iii)(b) of clause 3.1 is replaced by the following:

For the transfer price of fuel, in case of fuel specific procurement enquiry, if such price has not been determined by government, the concerned government-owned coal company, government approved mechanism or a fuel regulator (under Case 2).

2.5 The first paragraph of clause 3.2 is replaced by the following:

(I) In order to ensure timely commencement of supply of electricity being procured and to convince the bidders about the irrevocable intention of the procurer, it is necessary that various project preparatory activities are completed in time. For long-term procurement for projects for which pre-identified sites are to be utilized (Case 2), the following project preparatory activities should be completed by the procurer, or authorized representative of the procurer, simultaneously with bid process adhering to the milestones as indicated below:

2.6 The following paragraph is added at the end of clause 3.2:

(II) In Case-1 procurement, to ensure serious participation in the bid process and timely completion of commencement of supply of power, the bidder, in case the supply is proposed from a station to be set-up, should be required to submit along with its bid, documents in support of having initiated specific actions for project preparatory activities in respect of matters mentioned in (i) to (v) below.

- i) Site identification and land acquisition: Requirement of land would be considered as indicated in the proposal filed with the competent authority for seeking environmental clearance. The Bidder should have acquired and taken possession of at least 50% of the area of the land. In case of land to be acquired under the Land Acquisition Act 1894, the Bidder shall submit copy of notification issued for such land under Section 4 of the Land Acquisition Act 1894. In all other cases, the Bidder shall furnish documentary evidence in the form of certificate by concerned and competent revenue / registration authority for the acquisition / ownership / vesting of the land. These evidences shall be supported by a sworn affidavit from the developer listing the total land acquired for the power station.
- ii) Environmental clearance for the power station: The Bidder shall have submitted the requisite proposal, for the environmental clearance, to the concerned administrative authority responsible for according final approval in the central/state govt. as the case may be.

- iii) Forest Clearance (if applicable) for the land for the power station: The Bidder shall have submitted the requisite proposal, for the forest clearance, to the concerned administrative authority responsible for according final approval in the central/state govt. as the case may be.
- iv) Fuel Arrangements: Fuel arrangements shall have to be made for the quantity of fuel required to generate power from the power station for the total installed capacity of for the term of the PPA.
- In case of domestic coal, the Bidder shall have made firm arrangements for fuel tie up either by way of mine allocation or fuel linkage
 - In case of imported coal, the Bidder shall have either acquired mines having proven reserves for at least 50% of the quantity of coal required OR shall have a fuel supply agreement for at least 50% of the quantity of coal required for a term of atleast five (5) years or the term of the PPA, which ever is less
 - In case of domestic gas, the Bidder shall have made firm arrangements for fuel tie up by way of long term fuel supply agreement
 - In case of RLNG, the Bidder shall have made firm arrangements for fuel tie up by way of fuel supply agreement for at least 50% of the quantity of fuel required for a term of atleast five (5) years or the term of the PPA, which ever is less.
- v) Water linkage: The Bidder shall have acquired approval from the concerned state irrigation department or any other relevant authority for the quantity of water required for the power station.

If the Bidder is a trading licensee, it shall have executed exclusive power purchase agreement(s) for the quantity of power offered in its Bid and shall provide a copy of the same as part of its Bid. In such a case, the Bidder shall ensure that the entity with whom it has executed the exclusive power purchase agreement for supply of power under the bid process has completed the project preparatory activities as mentioned in (i) to (v) above. Furthermore, the Bidder shall be responsible for procuring from the entity developing the power station and submitting in its Bid, all the documentary evidence to establish that the project preparatory activities as in (i) to (v) above have been completed. In case of supply being proposed from an existing generating station, the Bidder should submit evidence in the form of a declaration sent to RLDC/SLDC, as the case may be, in support of commercial operation of the generating station.

2.7 The clause 4.1 is replaced by the following:

For procurement of electricity under these guidelines, tariff shall be paid and settled for each payment period (not exceeding one month). A multi-part tariff structure featuring separate capacity and energy components of tariff shall ordinarily form the basis for bidding.

Procurement under case-2 where procurer offers a captive fuel source (such as captive coal mine) for concurrent development and use for power production covered under the procurement query would also have a multi-part tariff structure featuring separate capacity and energy components of tariff.

2.8 Second proviso to be added in clause 4.3:

Provided further that the foreign exchange rate variation would be permitted in the payment of energy charges [stipulated in para 4.11 (iii)] if the bidder chooses to supply power using imported coal or imported gas (RLNG) for long term procurement under Case-1.

2.9 The clause 4.4 is replaced by the following:

Capacity charge shall be paid based on actual availability, as per charges quoted in Rs/kwh and shall be limited to the normative availability. The normative availability for Case-1 and thermal stations shall be a maximum of 85%. For hydro electric stations under case-2, the normative availability shall be at the level of normative annual plant availability factor as specified in the tariff regulations of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) prevailing at the time of the bid process. The capacity component of tariffs may feature separate non-escalable (fixed) and escalable (indexed) components. The indices to be adopted for escalation of the escalable component shall only be Wholesale Price Index (WPI), Consumer Price Index (CPI) or a combination of both WPI and CPI and the Base year shall be specified in the bid document.

2.10 Clause 4.5 is replaced by the following:

Capacity charges for availability beyond the normative availability shall be a pre-specified percentage of the non-escalable component of the capacity charges. The percentage applicable shall be specified in the RFP, and shall be limited to a 40% of the non-escalable component of the capacity charges. The procurer shall have first right of refusal on energy generated beyond normative availability. In case actual availability is less than the normative availability, capacity charges shall not be payable for the shortfall compared to the normative availability. In case availability is lower than a predetermined level (which is identified in the RFP and may be about 5% below normative availability), penalty at the rate of 20% of the capacity charge shall also be applicable to the extent of the shortfall in availability below such predetermined level.

2.11 The sub-clause (iii) of clause 4.11 replaced by the following:

In cases where the procurer mandates use of imported fuel for use in a coastal power station in Case-2 procurement query or where the bidder chooses to supply from a

power station using imported fuel under Case-1, the bids may be invited for base energy charge for the first year to be escalated as per the indices identified in the RFP. Such energy charge would have following three components:

- (a) Imported fuel component in US Dollars/unit.
- (b) Transportation of fuel component in US Dollars/unit.
- (c) Inland fuel handling component in Indian Rupees/unit

2.12 The following sub-clause (iv) to be added after sub-clause (iii) of clause 4.11:

- (iv) In case of linkage-based domestic coal/gas/imported fuel based projects, involving substantial inland transportation, a separate escalation component for inland transportation in Rupees / unit would be applicable.

Each of these components in (iii) and (iv) above may have separate non-escalable (fixed) and escalable (indexed) sub-components. The escalation indices for escalable sub-components of these components would be as notified by the CERC under para 5.6(vi).

It is clarified that the bidders would have option to quote firm energy charge rates for each of the years of the contract.

2.13 Clause 4.13 is replaced by the following:

In case a procurer invites bids of hydro power under Case 2, the hydrological risk shall be borne by the Procurer, provided the hydrological data of such a project is based on authentic sources and is known to the parties in advance. Any hydrological advantages under Case 2, resulting in energy availability beyond the design energy shall be passed on to the Procurer without any charge. In case a bidder offers hydro power under Case 1, the hydrological risk shall be borne by the Bidder. The geological risk for the hydro project in both Case 1 and in Case 2 shall be borne by the developer.

2.14 Clause 4.15 is replaced by the following:

In cases where the procurement process permits bidders to submit combined capacity and energy charges, the charges proposed shall be firm for each of the years of the term of the Power Purchase Agreement (PPA), and no escalation of tariff shall be permitted over and above the rates quoted by the seller in the price bid.

2.15 In Clause 5 after heading "Bidding Process" the words "Two-stage process" stands deleted.

2.16 Clause 5.1 is replaced by the following:

For long-term procurement under Case 2, a two-stage process featuring separate Request for Qualification (RFQ) and Request for Proposal (RFP) stages shall be adopted for the bid process under these guidelines. The procurer may, at his option, adopt a single stage tender process for long term or medium term procurement under Case 1, combining the RFP and RFQ processes. However, as specified earlier in para 2.2, the Procurer shall adopt separate RFP processes for procuring base load or peak load or seasonal load requirements, as the case may be. Procurer or authorized representative shall prepare bid documents including the RFQ and RFP (only RFP in single stage process) in line with these guidelines and standard bid documents.

2.17 Clause 5.2 is replaced by the following:

The procurer shall publish a RFQ (RFP in single stage process) notice in at least two national newspapers, company website and preferably in trade magazines also to accord it wide publicity. The bidding shall necessarily be by way of International Competitive Bidding (ICB). For the purpose of issue of RFQ (RFP in single stage process) minimum conditions to be met by the bidder shall be specified by the procurer in the RFQ (RFP in single stage process) notice.

2.18 The first sentence of clause 5.4 and its sub-clause (i) is replaced by the following:

Standard documentation to be provided by the procurer in the RFQ (RFP in single stage process) shall include,

(i) Definition of Procurer's requirements, including:

- Quantum of electricity proposed to be bought in MW. To provide flexibility to the bidders, this may be specified as a range, within which bids would be accepted. Further, the procurer may also provide the bidders the flexibility to, bid for a part of the tendered quantity, subject to a given minimum quantity;
- The procurer shall specify the nature of load requirement (either base load or seasonal load or diurnal load), the duration in months for which proposed power is being contracted for seasonal procurement, and duration in hours for which power is proposed to be contracted for diurnal requirement;
- Term of contract proposed: As far as possible in Case 2, it is advisable to go for contract coinciding with life of the project in case of long term procurement. The bidder shall be required to quote tariff structure for expected life of the project depending upon fuel proposed by him. The expected life project is estimated to be 15 years for gas/liquid fuel based projects, 25 years for coal based projects and 35 years for hydro projects. In Case 1, the procurer shall be free to specify the term of the contract for a specific bid process irrespective of the source of supply of power.
- Normative availability requirement to be met by seller (separately for peak and off-peak hours, if necessary);
- Definition of peak and off-peak hours, if relevant for the procurement query;

- Expected date of commencement of supply;
- Point(s) where electricity is to be delivered;
- Wherever applicable, the procurer may require construction milestones to be specified by the bidders;
- Financial requirements to be met by bidders including minimum net-worth etc with necessary proof of the same as required in the bid documents.

2.19 Clause 5.5 is replaced by the following:

RFP shall be issued to all bidders who have qualified at the RFQ stage in a two-stage bidding process. In case the bidders seek any deviations and the procurer finds that the deviations are reasonable, the procurer shall obtain approval of the Appropriate Commission before agreeing to the deviations. The clarification/revised-bidding document shall be distributed to all who had bought the RFP document informing about the deviations and clarifications and an intimation shall also be sent to the Appropriate Commission. Final PPA shall also be displayed on the website of the procurer. Wherever revised bidding documents/amendments are issued, the procurer shall provide bidders at least sixty (60) days in case of two stage bidding process and at least forty-five (45) days in case of a single stage bidding process after issue of such documents for submission of bids. However, a lesser time may be given for submission of RFP bids after any such revision/amendments in the RFP documents, with the written consent of all the pre-qualified bidders who have bought the RFP.

2.20 The sub-clause (ii) of clause 5.6 is replaced by the following:

PPA proposed to be entered with the selected bidder.

The model PPA proposed in the bidding documents may be amended based on the inputs received from the interested parties, and shall be provided to all parties responding to the RFP. No further amendments shall be carried out beyond the RFP stage;

2.21 The sub-clause (iii) of clause 5.6 is replaced by the following:

Payment security to be made available by the procurer.

The payment security indicated in the bidding documents could be modified based on feedback received during the bid process and as specified in the bid documents. However no further amendment to payment security would be permissible beyond the RFP stage.

2.22 The second paragraph of sub-clause (iv) of clause 5.6 is replaced by the following:

For the purpose of bid evaluation in cases other than where a captive fuel source is offered, escalation rate, as notified by the CERC from time to time on the basis of historical data, of the relevant fuel index (as identified in the RFP) in the international market or domestic market as the case may be, shall be used for escalating the energy charge (or the derived energy charge in cases referred to in

clause 4.2) quoted by the bidders. The provisions of clauses 4.11(iii) and (iv) would also apply to evaluation of bids in cases where the procurer mandates use of imported fuel for coastal power stations. However, in cases where the bidder quotes firm energy charges for each of the years of proposed supply, the energy charges proposed by the bidder shall be adopted for bid evaluation.

2.23 Sub-clause (vi) of clause 5.6 is replaced by the following:

Following shall be notified and updated by the CERC every six months:

1. Escalation rate for domestic coal. (Separately for evaluation and payment)
2. Escalation rate for domestic gas. (Separately for evaluation and payment)
3. Escalation rates for different escalable sub-components of energy charge for plants based on imported coal. (Separately for evaluation and payment)
4. Escalation rates for inland transportation charges for coal (Separately for evaluation and payment)
5. Escalation rates for inland transportation charges for gas (Separately for evaluation and payment)
6. Escalation rate for different escalable sub-components of energy charge for plants based on imported gas. (Separately for evaluation and payment)
7. Inflation rate to be applied to indexed capacity charge component.
8. Inflation rate to be applied to indexed energy charge component in cases of captive fuel source.
9. Discount rate to be used for bid evaluation.
10. Dollar-Rupee exchange variation rate. (For the purpose of evaluation)
11. Escalation for normative transmission charges (For the purpose of evaluation)

2.24 Clause 5.14 is replaced by the following:

In the case of procurement under Case-1,

- (i) the bidder shall quote the price of electricity at the interconnection point, i.e., being the point where the electric lines of the generating station connect to inter/intra state transmission network. For the purposes of standardisation in the process of bid evaluation, the tariffs shall be compared at the delivery point, i.e., the interface with the STU network in the procurer's state where power is delivered to the procurers. For generation source in the state of the procurer, the delivery point shall be the generation switchyard. Bid evaluation shall duly consider normative transmission charges, if any, from the injection point, i.e., the CTU interface point, to the delivery point with respective escalations provided by the CERC. Transmission losses from the interconnection point to the delivery point, as specified by the Appropriate Commission shall also be considered for evaluation and reflected in the final levelised tariff;

ii) actual transmission charges, as specified by the Appropriate Commission, from the injection point to the delivery point shall be borne by the procurers. Charges up to the injection point shall be borne by the bidder.

2.25 Clause 5.16 is replaced by the following:

In case there is any deviation from these guidelines, the same shall only be with the prior approval of the Appropriate Commission. The Appropriate Commission shall decide on the modifications to the bid documents within a reasonable time not exceeding 90 days.

2.26 Clause 5.19 is replaced by the following:

In the single stage bid process, a minimum period of 75 days shall be allowed between the issuance of RFP documents and the last date of bid submission. The timetable for the bid process is indicated in Annexure-II. In normal circumstances, the bid process is likely to be completed in a period of 120 days.

The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-II. However, if the bidding process is likely to take more than 195 days, approval of the Appropriate Commission shall be obtained in accordance with clause 5.16.

2.27 Clause 6.1 is replaced by the following:

The PPA shall be signed with the selected bidder/SPV (after its acquisition by the selected bidder under Case-2) consequent to the selection process in accordance with the terms and conditions as finalized in the RFP bid documents.

For cases referred to in clause 3.4 of these Guidelines, the PPA and other project documents may be executed by the SPV and the concerned parties prior to the last date of submission of RFP bids.

2.28 Clause 6.2 is replaced by the following:

After the conclusion of bid process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RFP bids shall provide appropriate certification on conformity of the bid process evaluation according to the provisions of the RFP document. The procurer shall provide a certificate on the conformity of the bid process to these guidelines.

2.29 The annexure-II of the existing guidelines is being replaced by the following:

Annexure-II: Time Table for single stage bid process

Sl. No.	Event	Activities to be completed by the Bidder prior to submission of Bid	Elapsed Time from Zero date
1.	Date of issue of RFP		Zero date
2.	Bid clarification, conferences etc. & revision of RFP		**
3.	RFP Bid submission	<ul style="list-style-type: none"> - Land: Should have acquired and taken possession of at least 50% of area of land. Section 4 notification shall be submitted in case land is acquired under the Land Acquisition Act, 1894. - Environmental clearance: Requisite proposal for the environmental clearance to the concerned authority should have been submitted - Forest Clearance(if required): Requisite proposal for the environmental clearance to the concerned authority should have been submitted. - Fuel Arrangement: Fuel arrangements by way of mine allocation/fuel linkage/fuel supply agreements should be available - Water linkage: Approval from the concerned state irrigation department or any other relevant authority should be available. 	75 days
4.	Evaluation of bids and issue of LOI		100 days

Sl. No.	Event	Activities to be completed by the Bidder prior to submission of Bid	Elapsed Time from Zero date
5.	PPA becomes effective: Signing of Agreements: i) Power purchase agreement, escrow agreement, hypothecation agreement and any other agreement as applicable (if these have not been already signed under clause 3.4). ii) Signing of share purchase agreement and transfer of SPV, if applicable.		120 days

**** In case of any change in RFP document, the procurer shall provide bidders additional time in accordance with clause 5.5.**

Note: It is clarified that if the procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from these Guidelines. However, if the bidding process under Case-1 procurement is likely to take more than 195 days, approval of the Appropriate Commission shall be obtained in accordance with clause 5.16.

MALAY SHRIVASTAVA, Director